श्री सभापति: थैंक यू, प्रश्न संख्या 63 ...**(व्यवधान)**...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ: माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में, महेश्वर में नर्मदा नदी के जो घाट हैं ...

MR. CHAIRMAN: No supplementaries on supplementaries. ...*(Interruptions)*... No, please. Please resume your place. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ: माननीय सभापति महोदय, वे बहुत खूबसूरत घाट हैं, वे डैमेज हो रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please resume your place. Question No.63.

दिल्ली और बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय

*63. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आज भी देश के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में अत्याधिक अन्तर बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली और बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय में बहुत अधिक अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो क्रमश: दिल्ली और बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय कितनी-कितनी है; और

(घ) उक्त राज्यों में क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक आय कितनी-कितनी है और क्या बारहवीं पंच-वर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर इस अन्तर को समाप्त किया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी हां। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) द्वारा मापी गई विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) विवरण-। पर दी गई है (नीचे देखिए)। वर्ष 2010-11 के दौरान बिहार के लिए अनुमानित 20069 रुपये की तुलना में दिल्ली की पीसीआई 135814 रुपये अनुमानित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान बिहार की पीसीआई की औसत विकास दर दिल्ली के साथ तुलनीय है। वास्तव में, इस अवधि के दौरान दिल्ली की 14.66% पीसीआई विकास दर की तुलना में बिहार ने 18.4% की वार्षिक औसत पीसीआई विकास दर हासिल की है।

(घ) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच राज्य विशिष्ट पीसीआई के वितरण संबंधी डेटा संग्रहित नहीं हुआ है, तथापि, प्रत्येक राज्य के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) का ग्रामीण शहरी क्षेत्र वार वितरण

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए घरेलू उपभोग व्यय संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर एकत्रित किया जाता है। वर्ष 2009-10 हेतु कराये गये नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार एवं दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में एमपीसीई क्रमशः 681 रुपये एवं 1566.5 रुपये था तथा शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 1092.33 रुपये एवं 2181.98 रुपये था।

अन्तर-राज्यीय असमानताओं एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं में कमी करना हमेशा विकास नीति की प्राथमिकता रही है तथा सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यनीति ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को सृजित करना, ग्रामीण अवसंरचना विकसित करना तथा स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता इत्यादि तक बेहतर पहुंच प्रदान करना रही है जिससे कि ग्रामीण जनसमूह के रहन-सहन स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार लाया जा सके। अन्तर-राज्यीय असमानता को न्यूनतम करने हेतु नीतिगत उपायों में कम विकसित राज्यों को वरीयता देते हुए राज्यों को केन्द्र से संसाधनों का योजना एवं गैर-योजना अंतरण, पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योगों की स्थापना हेतु कर लाभ इत्यादि शामिल हैं। राज्य के बीच आय विषमता को कम करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ, जिसमें 250 पिछड़े जिलों को कवर करते हुए जिला घटक, बिहार एवं उड़ीसा के केबीके जिलों हेतु विशेष योजना, 60 जनजातीय एवं पिछड़े जिलों हेतु एकीकृत कार्ययोजना और बुंदेलखंड हेतु सूखा शमन पैकेज शामिल है), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें एवं राज्य विशिष्ट स्कीमों से विभिन्न राज्यों की जीएसडीपी की विकास दर में तेजी आने की संभावना है।

विवरण-I

चालू कीमतों (2004-05 श्रृंखला) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय (रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	51025	60458
2	अरुणाचल प्रदेश	51405	एनए
3	असम	27197	30413
4	बिहार	16715	20069
5	झारखंड	27132	29786
6	गोवा	132719	एनए
7	गुजरात	63961	एनए
8	हरियाणा	78781	92327

1	2	3	4
9	हिमाचल प्रदेश	50365	58493
10	जम्मू व कश्मीर	30582	33056
11	कर्नाटक	52097	59763
12	केरल	59179	एनए
13	मध्य प्रदेश	27250	एनए
14	छत्तीसगढ़	38059	44097
15	महाराष्ट्र	74027	83471
16	मणिपुर	27332	29684
17	मेघालय	43555	48383
18	मिजोरम	45982	एनए
19	नागालैंड	एनए	एनए
20	उड़ीसा	33226	36923
21	पंजाब	60746	67473
22	राजस्थान	34042	39967
23	सिक्किम	68731	81159
24	तमिलनाडु	63547	72993
25	त्रिपुरा	35799	38493
26	उत्तर प्रदेश	23395	26051
27	उत्तराखंड	59774	68507
28	पश्चिम बंगाल	41219	एनए
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	74340	एनए
30	चंडीगढ़	118136	128634
31	दिल्ली	116886	135814
32	पांडिचेरी	88158	98719
	अखिल भारत एनएनआई (2004-05 श्रृंखला)	46492	54835

नोट: एनए- उपलब्ध नहीं।

स्रोत: क्रम सं. 1-32 हेतु - संबंधित/राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा अखिल भारत-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

Monthly Per Capita Income in Delhi and Bihar

†*63. SHRI RAM JETHMALANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that even today there exists a wide difference in per capita income in States of the country;

(b) if so, whether it is a fact that there is a wide gap in monthly per capita income in Delhi and Bihar;

(c) if so, the monthly per capita income in Delhi as well as in Bihar; and

(d) the monthly per capita income in rural as well as urban areas of the above-mentioned States and whether priority would be given to bridging of this gap in the Twelfth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI ASHWANI KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. The Per Capita Income (PCI) of different States, measured by per capita Net State Domestic Product (NSDP) at current prices for the years 2009-10 and 2010-11, is given at Statement-I *(See* below). The PCI of Delhi during the year 2010-11 is estimated at Rs. 135814 as compared to that, of Bihar estimated at Rs.20069. During the first four years of the Eleventh Five Year Plan, the average growth rate of PCI of Bihar has been comparable to that of Delhi. In fact, during this period Bihar has registered an annual average PCI growth rate of 18.4% as compared to the PCI growth rate of Delhi estimated at 14.6%.

(d) The data on distribution of State specific PCI between rural and urban areas is not compiled. However, the rural urban area-wise distribution of Monthly Per Capita Consumption Expenditure (MPCE) for each State is compiled on the basis of the House Hold Consumption Expenditure Survey conducted by National Sample Survey Office (NSSO) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation. As per the latest survey conducted for 2009-10, the MPCE in the rural areas of Bihar and Delhi was Rs. 681 and Rs.1566.5 respectively and in urban areas it was Rs. 1092.33 and Rs. 2181.98 respectively.

Reduction of inter-state disparities and inequalities between rural and urban areas has always been the priority of development policy and the Government is committed to it. The strategy has

†Original notice of the question was received in Hindi.

been to generate employment opportunities in rural areas, develop rural infrastructure and provide better access to health, education, drinking water, sanitation, etc. in order to bring a tangible improvement in standard of living and quality of life of the rural masses. The policy instruments for minimising the inter State disparity include plan and non-plan transfer of resources from the Centre to States favouring less developed States, tax incentives for setting up of private industries in the backward regions, etc. A number of programmes have also been initiated to reduce income disparity between States. These include Backward Regions Grant Fund (BRGF), which includes the district component covering 250 backward districts, special plan for Bihar and the KBK districts of Orissa, the Integrated Action Plan for 60 tribal and backward districts and the drought mitigation package for Bundelkhand), Hill Area Development Programme/Western Ghats Development Programme and Border Area Development Programme, etc. In addition, several ongoing Centrally Sponsored Schemes and State specific schemes are expected to accelerate the growth rate of GSDP of various States.

Statement-I

Per-capita income of the States/UTs at current prices (2004-05 series)

(in Rupees)

Sl.No.	State/UT	2009-10	2010-11
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	51025	60458
2	Arunachal Pradesh	51405	NA
3	Assam	27197	30413
4	Bihar	16715	20069
5	Jharkhand	27132	29786
6	Goa	132719	NA
7	Gujarat	63961	NA
8	Haryana	78781	92327
9	Himachal Pradesh	50365	58493

1	2	3	4
10	J&K	30582	33056
11	Karnataka	52097	59763
12	Kerala	59179	NA
13	Madhya Pradesh	27250	NA
14	Chhattisgarh	38059	44097
15	Maharashtra	74027	83471
16	Manipur	27332	29684
17	Meghalaya	43555	48383
18	Mizoram	45982	NA
19	Nagaland	NA	NA
20	Orissa	33226	36923
21	Punjab	60746	67473
22	Rajasthan	34042	39967
23	Sikkim	68731	81159
24	Tamil Nadu	63547	72993
25	Tripura	35799	38493
26	Uttar Pradesh	23395	26051
27	Uttarakhand	59774	68507
28	West Bengal	41219	NA
29	A & N Island	74340	NA
30	Chandigarh	118136	128634
31	Delhi	116886	135814
32	Pondicherry	88158	98719
	All India NNI(2004-05 series)	46492	54835

Note: NA: Not Available

Source: For Sl.No. 1-32 - Directorate of Economics & Statistics of respective State Governments, and for All-India - Central Statistical Organisation

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I have gone through the very confidential reply and the figures that the hon. Minister has supplied to us. But in the last sentence of that reply I find a somewhat vague statement. Could you possibly give us a list of the Centrally-sponsored but Bihar-specific schemes which, according to you, create the hope that this disappointing disparity will soon be revoked?

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, as the hon. Member is fully aware, there are in all 147 Centrally-sponsored schemes in existence today. The hon. Member has asked for State-specific schemes for Bihar. I will give him the list. But I can tell the Member and also this House, through you, Sir, that Bihar has got a special plan for its development and, over the years, I am delighted to point out that the level of economic development of Bihar has been rather good. In fact, it has grown at an average rate of 18.4 per cent as against Delhi's growth rate of 14.6 per cent. Of course, it is a function of the low base from which Bihar started. But in the last several years we have seen that there has been a marked improvement in the overall development.

Sir, the most important, I think, part of the question and the focus of the hon. Member's question is the uneven economic development in the country. It is a reality and I accept that it is a reality and it needs to be addressed. For this reason, the objective of the Eleventh and Twelfth Five Year Plans has been inclusive, sustainable and faster growth, and the real mechanism for ensuring even economic development is to achieve overall growth in the agricultural sector because it leads over time to a more broad-based growth. That is precisely the focus of the Twelfth Plan which is under formulation.

I may also point out, Sir, that there are a number of programmes including the Backward Regions Grant Fund which addresses the development needs of the 250 backward districts which are spread all over the country. I would like to inform the hon. Member and the House, through you, Sir, that I have myself initiated a discussion on seeking ways to address the income and economic development disparities on a district-wise basis throughout the country.

Not only is there an uneven economic development as far as the States are concerned, there is also an uneven economic development within the States and the reasons are district specific. So, I would like to assure the House and the hon. Member that through a series of policy interventions we are seeking to address the issue of income and economic disparities.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I must compliment the Minister. Even he knows how much of respect and affection he enjoys from me. But, Sir, I am entitled to ask, "Has there been any serious study conducted during the last few years to deal with this somewhat dismal economic situation of this State?" If there is a real serious study done, then please tell us what proposals that study has yielded that the condition of Bihar could be improved. You see in this long list, Bihar is, practically, the last. Why is it so? It is a tragic state of affairs.

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, as I said, as far as Bihar is concerned, there is a specific plan for Bihar, a special development plan for Bihar, which addresses almost all the issues that are specific to Bihar. That process is on. Of course, there has been a request from Bihar in the last several years. But that is a matter which the NDC has to take a call on. But I would like to assure him that through a series of policy interventions specific to Bihar, the Government of India in consultation with the State Government of Bihar, is taking steps to address this issue.

श्री रामविलास पासवान: महोदय, बिहार का जो 2010-11 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसके मुताबिक बिहार पर 57,664 करोड़ रुपये का कर्जा है, मतलब जो भी बच्चा है, उसके ऊपर 5,700 रुपए का कर्जा है। बिहार का जो अपना राजस्व है, वह 11,000 करोड़ है। हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारत सरकार ने अकेले केन्द्रीय राजस्व से 2010 में साढ़े 35 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, जो पेंशन है, वेतन है और जो कर्जा है, उसके ऊपर ही 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री रामविलास पासवान: मैं यह जानना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: ये बिहार के पक्ष में खड़े हैं या बिहार के विरोध में खड़े हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: तिवारी जी, एक मिनट बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... पासवान जी, आप अपना सवाल पूछिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: ये जवाब दे रहे हैं या सवाल कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: रूडी जी, प्लीज़ बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Please put your question. No statement, please. Put your question.

श्री शिवानन्द तिवारी: ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: क्या यह सही है कि केन्द्र का जो पैसा बिहार में जा रहा है, सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है? यह सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 67,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। ...**(व्यवधान)**... क्या सरकार इसकी जांच कराएगी? ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: सब असत्य बोल रहे हैं। सीएजी ने नहीं कहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं इनको चुनौती देता हूं। ...**(व्यवधान)**... सीएजी ने नहीं कहा है। यह मामला हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट में सीएजी ने कहा है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please resume your place. Please allow the Question Hour to proceed. Mr. Minister, is there any answer to this? ...*(Interruptions)*... If there is no question, there is no answer. ...*(Interruptions)*...

श्री शिवानन्द तिवारी: कोई स्कैम नहीं है। ...**(व्यवधान)**... जनता से खारिज आदमी हैं, लोक सभा का चुनाव हार गए। ...**(व्यवधान)**... यह क्या राजनीति कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव प्रताप रूडी: केवल पांच सीटें रह गयी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: यह कोई आंसर देने की बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**... इसका सवाल से क्या रिश्ता है? ...**(व्यवधान)**... वे कौन सा जवाब मांग रहे हैं? उनका सवाल है ही नहीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: मेरा सवाल यह है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: पासवान जी, बैठ जाइए प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ASHWANI KUMAR: This question has no relation, whatsoever, to the main question.

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, इसमें केवल बिहार ही नहीं है, दूसरी स्टेट भी हैं, उड़ीसा भी है। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, the Minister, in his reply to the first supplementary raised by the hon. Member, has said that he is concerned not only about inter-State disparities/inequalities, but also the disparities/inequalities within the State and within districts, and therefore, that they have some policy instruments to deal with that. Today, I think, the most basic inequality is the inequality between individuals. In fact, per capita calculations conceal these inequalities. When we talk about

policy instruments, my supplementary to the hon. Minister is: What are the policy instruments which the Government is going to use to deal with the huge, obscene inequalities which have been created by certain neo-liberal policies being pursued, interestingly, between individuals? And would the Minister consider using, as a policy instrument, the issue of universalisation of benefits considering that such a massive majority of our people are below the poverty line, in real terms and not by dubious methods of the Planning Commission. Therefore, my basic supplementary is: Would you consider universalizing the rights to food, education and health, to begin with, giving up the present policy instrument of targeting?

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, kindly allow me to respond to the hon. Member in the way that I must. First of all, the basic premise that the policies that have, over the years, assured for the country an overall growth rate of 8.5 per cent do not, eventually, endeavour to the benefit of the common man, is a flawed assumption. I would, with utmost humility and respect, like to say that the policy of the UPA Government, over the last several years, have enabled the country to achieve the highest possible growth rates which, in turn, have enabled us to mop up enough resources to divert and allocate the highest possible resources to sectors, to which the hon. Member refers, namely, education, health and food security. We have, in the past several years and also recently, repeatedly stated, in all the discussions in this House and outside, and in the Plan discussions, that the basic priority of this Government is inclusive, faster sustainable growth, the end result of which is even-handed economic development, the fruits of which would reach every citizen of the country over time. It is true, however, that every State, every Government and every country, eventually, has to work within the basket of resources available. One cannot win the extent and range of social welfare programmes without consideration of the resources actually available.

Therefore, our repeated effort has been to create a political consensus around policies that would generate more growth and, thereby, help us to alleviate poverty.

श्री गंगा चरण: सभापति जी, मैं यह सवाल प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, चूंकि सवाल बिहार का है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने बुंदेलखंड का भी जिक्र अपने उत्तर में किया है कि उन्होंने सूखे से निपटने के लिए बुंदेलखंड के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया है। आज बुंदेलखंड देश की राजनीति का केन्द्र बिंदु बन गया है। अभी प्रधान मंत्री जी बुंदेलखंड में बांदा गए थे और 200 करोड़ रुपये...।

श्री सभापति: सवाल बिहार पर है।

श्री गंगा चरण: सभापति महोदय, उन्होंने जो उत्तर दिया है, उसमें इसका जिक्र किया है। ...**(व्यवधान)**... प्रधान मंत्री जी ने इसका जिक्र किया है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: सर, इसमें अन्य राज्यों की भी चर्चा हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री गंगा चरण: बुंदेलखंड में जो आपने स्पेशल पैकेज दिया है drought को कम करने के लिए, सूखे को रोकने के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि उस स्पेशल पैकेज में किन-किन योजनाओं को शामिल किया गया है। चूंकि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। मैं देखता हूं कि अभी तक स्पेशल पैकेज की कोई शुरूआत ही नहीं हुई है, इसको दो साल होने जा रहे हैं और अभी आपने वहां जाकर 200 करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की थी। वह 200 करोड़ रुपया भी अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। इसलिए यह मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि बुंदेलखंड राजनीति का केन्द्र बिंदु बन गया है। राहुल गांधी आए दिन दौरा करते हैं, आपने भी दौरा किया, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के लिए केन्द्र सरकार ने क्या किया है, इसके बारे में आप बताइए? ...**(व्यवधान)**... आप दौरा करते हैं, सिर्फ भाषण ही देते हैं या कुछ करते भी हैं?

श्री अश्विनी कुमार: माननीय सदस्य ने बुंदेलखंड के मुतल्लिक जो सवाल पूछा है, वह इस सवाल से ताल्लुक नहीं रखता है, मगर मैं फिर भी आपको यह जानकारी देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि बुंदेलखंड का जो पैकेज प्रधान मंत्री जी ने एनाउंस किया है, वह कारगर कराया जा रहा है। उसकी बहुत बारिकी से मॉनिटरिंग हो रही है। ...**(व्यवधान)**... पीने के पानी की व्यवस्था का काम शुरू हो गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: कितना पैसा दिया है? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... We will move on to the next Question. *...(Interruptions)...*

श्री अश्विनी कुमार: बात को कर लेने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... अगर आप सुनेंगे तो मैं बात कहूंगा। ...**(व्यवधान)**... आप बात सुनेंगे, तो मैं बात कहूंगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Let us move on to the next Question.

श्री विनय कटियार: आधे घंटे की चर्चा करा लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अली अनवर अंसारी: सर, इस आधे घंटे की चर्चा करा लीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Just one minute please. आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट बैठ जाइए। अली अनवर जी, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़। Hon. Members, please. *...(Interruptions)...* आप एक मिनट जरा बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

Mr. Pany, please प्लीज़ बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Just one minute. प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आप नोटिस दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

Hon. Members, supplementary questions on Starred Questions is a courtesy extended to individual Members. Now, it is a window; it is not an elephant gate. Please do not try to expand what should be a question into what should be the subject of a proper discussion. You know the procedures. Give notice. Question 64.

श्री मोती लाल वोरा: क्वेश्चन 64 ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: देखिए, आप नोटिस दीजिए। ...**(व्यवधान)**... तिवारी जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, बिहार में ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Question 64. Please आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Please, तिवारी जी, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: हम बिहार के रहने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि बिहार में ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: जो पैसा बिहार सरकार को दिया गया है, उसका कितना सदुपयोग किया गया है? ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: बिहार में ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: वहां की सरकार पूरी तरह विफल है। ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: इस हाउस में बिहार का ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: न कोई आपकी बात सुन रहा है और न कोई देख रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: चाहे वहां राजीव गांधी विद्युतीकरण की योजना हो ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: वहां पर पूरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी: आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: CAG ने बिहार सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, CAG की रिपोर्ट आई है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... I will name you. ...*(Interruptions)*...

श्री तारिक अनवर: उसकी जांच होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। अपनी जगह पर वापस जाइए और वहां से बोलिए। ...**(व्यवधान)**... Hon. Members, please allow the Question Hour to proceed.

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, हम लोगों को बहुत खेद है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप discussion मांगिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: सर, CAG की रिपोर्ट बिहार सरकार के खिलाफ आई है। ...**(व्यवधान)**...

बिहार सरकार के कार्यकलापों के खिलाफ सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई है ...**(व्यवधान)**... बिहार सरकार के खिलाफ सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई है ...**(व्यवधान)**... पैसे का दुरुपयोग किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनीति प्रसाद: सभापति जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़, आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... राजनीति जी ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... Voraji, please ask your question.

श्री विनय कटियार: मैं सोचता हूं कि यह देश के विभिन्न राज्यों का भी सवाल है, यह केवल बिहार का सवाल नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सभापति जी, बिहार ...**(व्यवधान)**...

श्री अली अनवर अंसारी: सभापति जी ...**(व्यवधान)**... हमको मौका नहीं दिया है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: वह सवाल खत्म हो गया है ...**(व्यवधान)**... देखिए, आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... आपकी बात न तो कोई सुन रहा है ...**(व्यवधान)**... न कोई देख रहा है ...**(व्यवधान)**... आप प्लीज़ बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद अली खान: पैसे की कमी नहीं रखते ...**(व्यवधान)**... यूपीए सरकार ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: आप इतनी वकालत कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please allow Q. No. 64. आप प्रश्न पूछिए ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप नोटिस दीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: सभापति जी ...**(व्यवधान)**... बुंदेलखंड का क्वेश्चन पूछा है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़ आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... वोरा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए ...**(व्यवधान)**...

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मुझे मूल प्रश्न ही पूछना था ...**(व्यवधान)**... मैंने मूल प्रश्न ही नहीं पूछा ...**(व्यवधान)**...

श्री अली अनवर अंसारी: आज दर्जे में स्पेशल कैटेगिरी है बिहार की ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, प्लीज ...**(व्यवधान)**... वोरा जी, आप प्रश्न पूछिए ...**(व्यवधान)**...

मलेशिया में बंधक बनाए गए भारतीय श्रमिक

*64. **श्री मोती लाल वोरा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मलेशिया की जे.एम. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड कम्पनी ने जनवरी, 2011 से बिहार के 17 मजदूरों को गलत तरीके से बन्दी बना कर रखा हुआ है और उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जा रही है; और

(ख) सरकार ने उनकी रिहाई, उन्हें भारत वापस लाये जाने और उनका वेतन दिलाए जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) झारखंड राज्य के रहने वाले और मलेशिया की कंपनी मैसर्स जे.एन. पावर कंस्ट्रक्शन (एम) एसडीएन, बीएचडी द्वारा 28-11-2009 से तीन वर्ष के लिए नौकरी पर रखे गय सत्रह भारतीय राष्ट्रिकों ने क्वालालम्पुर स्थित भारतीय उच्चायोग को 22.06.2011 को शिकायत की कि उन्हें जनवरी, 2011 से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। चूंकि श्रमिकों ने नौकरी छोड़ दी थी, इसलिए उनके रहने और खाने की व्यवस्था उच्चायोग द्वारा की गयी।

(ख) भारतीय उच्चायोग ने उनकी समस्या हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- उच्चायोग ने तत्काल (23.06.2011 को) नियोक्ता को मिशन परिसर में बुलाया और संबंधित भारतीय राष्ट्रिकों की मौजूदगी में मुद्दे पर उनके साथ चर्चा की। नियोक्ता सभी देयों का निपटान करने के लिए सहमत हो गया है।
- मिशन के प्रयासों से जनवरी और फरवरी माह की मजदूरी का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया। हालांकि मार्च से आगे का भुगतान करने के लिए भी सहमत होने के बावजूद कंपनी द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।